संपादकीय

खतरनाक मोड़ पर जातीय संघर्ष

मणिपुर में चरमपंथियों के बीच चल रहा अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौट कर प्रधानमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। उसमें उन्होंने मणिपुर में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करने और स्थिति को सामान्य बनाने के उपायों पर अमल करने का निर्देश दिया। मणिपुर में हिंसा भड़के दो महीने होने को हैं। दस हजार से अधिक लोग विस्थापित हैं। सौ से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों घायल हैं। हजारों दुकानें, घर, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जला दिए गए हैं। इसे लेकर कुछ दिनों पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसे लेकर विपक्षी दलों का आरोप है कि दस मिनट भी बातचीत नहीं हुई और बिना किसी सलाह के समाप्त हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री की बुलाई उच्चस्तरीय बैठक का मणिपुर की स्थिति पर कितना असर पड़ेगा, देखने की बात है। दरअसल, मणिपुर इस वक्त नाजुक दौर में पहुंच चुका है। फिर भी मणिपुर सरकार उस पर परदा डालने का प्रयास ही करती देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। मगर हकीकत यह है कि अब महिलाएं भी वहां सुरक्षाबलों के विरोध में सड़कों पर उतर आई हैं। कुकी और मैतेई चरमपंथियों के बीच चल रहा जातीय संघर्ष गृहयुद्ध का रूप लेता जा रहा है। ऐसी स्थिति में केवल बैठकों से कोई स्थायी समाधान शायद ही निकले। यह समझ से परे है कि केंद्र और राज्य सरकार ने वहां की स्थित से निपटने के लिए व्यावहारिक उपाय तलाशने के बजाय क्यों दोनों समुदायों को खुद इसका समाधान तलाशने के लिए छोड़ दिया है। इस बीच सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे। वहां के शस्त्रागार से करीब चौबीस सौ स्वचालित हथियार और भारी मात्रा में कारतूस-गोला-बारूद लूट लिया गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझ कर वे हथियार लुटवाए। मगर इस पर सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। अब कहा जा रहा है कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। विचित्र है कि जिस वक्त मणिपुर जल रहा है, उसे शांत करने के बजाय राजनीतिक रंग देकर अपनी जिम्मेदारियों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार वहां की जातीय हिंसा को रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। मणिपुर में हिंसक घटनाओं की शुरुआत हुई तो वहां के उच्च न्यायालय के एक अव्यावहारिक निर्देश की वजह से, मगर इसके मूल में सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया शुरू से ही देखा जा रहा था। कुकी और नगा जनजातियों के लिए आरक्षित पहाड़ी इलाकों से सरकार ने खुद तथाकथित बाहरियों को निकालने का अभियान शुरू किया था। उससे यही संदेश गया कि सरकार आरक्षित क्षेत्रों में मैतेई लोगों की घुसपैठ कराना चाहती है। फिर अदालत के मैतेई लोगों को जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार संबंधी निर्देश ने आग में घी का काम किया। ऐसे संवेदनशील मसले पर सरकार को भ्रम निवारण के व्यावहारिक उपाय करने चाहिए थे। केंद्र सरकार का भी रवैया इसे लेकर ढीलाढाला ही रहा है, वरना महज औपचारिकता के लिए न तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती और न हाथ पर हाथ धरे हिंसक झड़पों के अपने आप शांत होने का इंतजार किया जाता। जब तक वहां हिंसा नहीं रुकेगी, तब तक ईंधन और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति भी ठीक से बहाल नहीं हो सकेगी। हिंसा रोकने के लिए वहां के लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है।

देवशयनी एकादशी पर करें यह उपाय धन लाभ के साथ मिलेगी सुख शांति

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। वहीं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल 29 जून, बृहस्पतिवार को देवशयनी एकादशी है। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी वर्ष का वह दिन होता है जब भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर जागते हैं। मान्यता के अनुसार इस दौरान धरती का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस एकादशी तिथि को यदि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक विष्णु जी का पूजन करता है और कुछ उपाय करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

देवशयनी एकादशी के उपाय- देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख-शांति आती है।

इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर व्रत का पालन करें,विष्णु सहस्त्रनाम या गोपालसहस्त्राम का पाठ करें।ऐसा करने से आपकी संतान योग्य बनती है और उनके कष्टों का निवारण होता है।

आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जल में आँवले का रस डालकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और प्राणी के सारे पाप दूर हो जाते हैं।

देवशयनी एकादशी के दिन श्री नारायण का कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है।

शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती है। इसकी ध्वनि जहां तक पहुंचती है,सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है साथ ही वहां तक के वातावरण में रहने वाले सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूजा करने के उपरांत शंख का जल पूरे घर में छिड़क देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

देवशयनी एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो जरुरतमंदों को फल, दवाइयां और वस्त्र दान करने चाहिए। इससे आपको स्वयं मानसिक शांति अनुभव तो होता ही है साथ ही मान्यता है कि इससे व्यक्ति के रोग कटने लगते हैं और वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है।

इस दिन रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन-कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है। वह हज़ारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। इस दिन मंदिर, तुलसी के नीचे और नदियों के किनारे दीपदान करने से श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करके घर या मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर गीता का पाठ अवश्य ही करें, ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरो का आशीर्वाद मिलता है एवं घर के लोग तरक्की करते हैं।

तो दूर होगी हर समस्या

इस बार चातुर्मास चार माह की बजाय पांच माह तक रहेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के अलावा कुछ उपाय करने से जीवन में खुशियां आती हैं। चलिए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए।

सख-समृद्धि के लिए उपाय -यदि घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख-समृद्धि।

दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए - देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी से अपने अच्छे दांपत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

पैसों की तंगी दूर करने के लिए करें ये उपाय -देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान एक रुपए का सिक्का श्रीहरि विष्णु की फोटो के पास रख दें। फिर पूजा के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे भगवान विष्णु के साथ आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में धन-धान्य की कमी नहीं होगी।

जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए -देवशयनी एकादशी के दिन पूजा को दौरान भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।

मन पसंद विवाह के लिए -यदि आपके मन पसंद विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन बिछाकर उसपर बैठ जाएं। फिर विष्णु जी के मंत्र ऊँ नमो भगवते नारायणाय। का 11 बार जाप करें।

भारत-अमेरिका: प्रौद्योगिकी संचालित समान सहयोग के युग की शुरुआत

डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल ही में समाप्त हुई संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा इस अर्थ में ऐतिहासिक है कि इसने आने वाले वर्षों के लिए भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रौद्योगिकी संचालित समान सहयोग के युग में प्रवेश कर रहे हैं और यह सहयोग उस यात्रा की शुरुआत का प्रतीक हैए जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है। आकाश ही सीमा नहीं है।

वास्तव में इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है जिन्होंने पिछले 9 वर्षों के दौरान कई गैर परंपरागत और नयी राह दिखाने वाले अभिनव निर्णय लिएए जिनकी वजह से भारत प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हुआ। उदाहरण के लिएए संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने भारत से कई वर्ष पहले अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की थीए आज भारत को अपने भविष्य के प्रयासों में एक समान भागीदार के रूप में आमंत्रित करता है।

21 जून को वाशिंगटन स्थित विलार्ड इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में एक समारोह के दौरान भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया। आर्टेमिस समझौता, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए राष्ट्रों के बीच नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों के एक व्यावहारिक समूह की स्थापना करता है। यह भारत को चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम बनाता है। ध्यान देने योग्य है कि यह समझौता अंतरिक्ष क्षेत्र मेंए विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के आयात से जुड़े प्रतिबंधों में छूट देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिससे भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजारों के लिए प्रणाली विकसित करने और नवाचार करने में लाभ होगा। यह अन्य वैज्ञानिक कार्यक्रमों में भारत को संयुक्त रूप से भागीदार बनने की सुविधा प्रदान करेगाए मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों समेत विभिन्न गतिविधियों में दीर्घकालिक सहयोग के लिए सामान्य मानकों तक पहुंच की अनुमति देगा और माइक्रो, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम, अंतरिक्ष सुरक्षा आदि रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिका के साथ मजबूत भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगा।

आर्टेमिस समझौता एक गैर बाध्यकारी समझौता है, जिसके तहत कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। इस समझौते पर 13 अक्टूबर, 2020 को आठ संस्थापक राष्ट्रों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, यूएई, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे। इसके सदस्यों में जापानए फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगी देश शामिल हैं, जबकि रवांडा, नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देश नए भागीदार हैं। आइए, यह समझने की कोशिश करें कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने से भारत को क्या लाभ होगा। एक अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए वैश्विक सरकारी खर्च पिछले साल लगभग 103 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। लगभग 62 बिलियन डॉलर के साथए अमेरिकी सरकार ने अकेले कुल धनराशि का आधे से अधिक खर्च किया। अमेरिका के बाद चीन ने लगभग 12 बिलियन डॉलर खर्च किये, जो इस समूह का हिस्सा नहीं है। रूस 34 बिलियन डॉलर के वार्षिक खर्च के साथ 5वें स्थान पर है। भारत 193 बिलियन डॉलर के वार्षिक बजट के साथ 7वें स्थान पर है।

2014 से पहले, इसरो कभी-कभार उपग्रह लॉन्च करता थाए लेकिन पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की शुरुआत के बादए आज इसरो लगभग 150 निजी स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है। सुदूर अंतरिक्ष मिशनों के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होती है और इससे पूरी मानवता लाभान्वित होती है। इसलिएए यह जरूरी है कि राष्ट्र मानवता के लाभ के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करें। बिना समय गंवाएए समान विचारधारा वाले देशों को आगे आना होगाए सहयोग करना होगा और एक-दूसरे के लाभ और अनुभवों पर काम करना होगाए जैसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है, हमें अलग-थलग होकर काम नहीं करना चाहिए! अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत-अमेरिका के बीच नए सहयोग का पहला बड़ा स्पष्ट लाभ देखने के लिए हमें शायद लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। अगले साल एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस भेजा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के बाद व्हाइट हाउस में इसकी पुष्टि कर चुके हैं।

पीएम मोदी की मौजूदा यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि नासा अपने एक सुविधा केंद्र में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दोनों पक्षों के समानए अन्य क्षेत्रों के लिए भी परस्पर लाभ में तेजी देखने को मिलेगी। अमेरिकी मेमोरी चिप कंपनीए माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक ने गुरुवार को कहा कि वह भारत के गुजरात में एक नई चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा इकाई के लिए 825 मिलियन डॉलर तक का निवेश करेगी, जो देश में इसकी पहली निर्माण, इकाई होगी। केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से इस सुविधा केंद्र में 2.75 बिलियन डॉलर का कुल निवेश किया जाएगा।

राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी संयुक्त भारत.अमेरिका क्वांटम सहयोग व्यवस्था की स्थापना पर भी सहमत हुएए ताकि उद्योगए शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके तथा एक व्यापक क्वांटम सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते की दिशा में काम किया जा सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता; आई और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और व्यवसायीकरण और भारत में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग एचपीसी सुविधाओं को विकसित करने के क्रम में सार्वजनिक.निजी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यूएस, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकमुश्त निधि के तहत 2 मिलियन डॉलर का अनुदान कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

राष्ट्रपति बाइडेन ने एआई पर वैश्विक साझेदारी के अध्यक्ष के रूप में भारत को अमेरिकी समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों राजनेताओं ने गूगल के अपने 10 बिलियन डॉलर के भारत डिजिटलीकरण फंड के माध्यम से शुरुआती चरण के भारतीय स्टार्टअप तथा अन्य में निवेश जारी रखने के इरादे की सराहना की। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान, एक्सेलेरेटर की लॉन्ग बेसलाइन न्यूट्रिनो फैसिलिटी के सहयोगात्मक विकास के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग, डीओई की फर्मी नेशनल लेबोरेटरी को 140 मिलियन डॉलर का योगदान देगा, जो अमेरिका की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा केंद्र होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र मेंए दोनों देशों के अनुसंधान संस्थान किफायती कैंसर प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगे, जिनमें एआई सक्षम निदान और पूर्वानुमान भविष्यवाणी उपकरणों का विकास और मधुमेह अनुसंधान शामिल होंगे। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को गति देते हुए एयर इंडिया 34 बिलियन डॉलर में 220 बोइंग विमान खरीदेगी। भारत, अमेरिका संबंधों के सबसे अच्छे होने का सबसे स्पष्ट संकेत यह है किजैसा पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के अपने संबोधन में उल्लेख किया थाए अमेरिका आज न केवल भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग, भरोसेमंद संबंध को रेखांकित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की यात्रा के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य के समापन वाक्य का निष्कर्ष के तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। हमारी भारत और अमेरिका महत्वाकांक्षाएं और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की हैं।

लेखक केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं

देवशयनी एकादशी के दिन न करें ये गलतियां

इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 को रखा जा रहा है। यह व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इस दिन किए गए पूजन और दान-पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। चातुर्मास शुरू होने के बाद से सारे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र जिन्हें देवशयनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए।

तामसिक चीजों से रहें दूर-देवशयनी एकादशी के दिन पूर्ण रूप से सात्विक आचार-विचार रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तामसिक चीजें जैसे-मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी तरह का नशा भी नहीं करना चाहिए।

न खाएं चावल-देवशयनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यदि आप इस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो चावल न खाएं और न ही चावल से बनी अन्य चीजें जैसे पोहा, पुलाव आदि खाएं। एकादशी पर चावल खाने की सख्त मनाही है।

ब्रह्मचर्य का पालन-एकादशी के दिन सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें और भगवान के मंत्रों का जाप पूरे समय करते रहें।

मन में न लाएं बुरे विचार-देवशयनी एकादशी के दिन मन में किसी के प्रति बुरे विचार भी नहीं लाना चाहिए और न ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस दिन मन में सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखें।

नीतिगत बदलावों से ही फसल के सही दाम...

नजरिया -डॉ. वीरेन्द्र सिंह लाठर

वर्ष 2022-23 में धान किसानों को कम दाम मिलने से उनका एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान विभिन्न सरकारों की गलत नीतियों के कारण हुआ। बेशक सदियों से किसान के शोषण की वजह सामंती शासन व्यवस्था रही है। लेकिन आजाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उन किसानों का शोषण होना गंभीर विषय है ज़िन्होंने हरित क्रांति के तहत उन्नत बीज व महंगी तकनीक अपनाकर देश को बढ़ती आबादी के बावजूद खाद्यान्न में लगातार आत्मनिर्भर बनाये रखा। इन महंगी उन्नत तकनीक के उपयोग से बढ़ी कृषि लागत की भरपाई के लिए सरकार ने वर्ष 1966 में फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति को मंजूर किया। भारत में वैधानिक तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वह न्यायोचित उपयुक्त मूल्य है जो फसल बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलना ही चाहिए।

लेकिन साहूकार बिचौलियों की हितैषी व्यवस्था ने पिछले 57 वर्षों में अपने ही द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून नहीं बनाकर, कभी भी निजी व्यापारियों पर लागू नहीं किया और उन्हें कृषि उपज मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर, फसल उपज खरीद की अनुमति देकर किसानों का खुला शोषण होने दिया। इससे भी आगे, स्वामीनाथन राष्ट्रीय कृषि आयोग-2006 की सिफारिशों, कि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना सम्पूर्ण सी-2 लागत + 50 प्रतिशत लाभ पर होनी चाहिए', को नहीं लागू करके सरकारें स्वयं भी किसानों का नुकसान कर रही हैं। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 में देश में धान का कुल 130 करोड़ क्विंटल उत्पादन हुआ जिसमें से 11.3 करोड़ किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल पर सरकार ने 62 करोड़ क्विंटल धान की खरीद लगभग एक लाख साठ हजार करोड़ में की यानी स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश की गयी एमएसपी 2710 रुपये प्रति क्विंटल (सी-2 लागत 1805 रुपये + 50 प्रतिशत लाभ) पर खरीद नहीं करके किसानों का लगभग 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान किया गया! इतना ही नहीं, पिछले 65 वर्षों से एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाकर, बिचौलियों को भी किसानों को लूटने की एक तरह से छूट दे रखी है ज़िन्होंने बाकी बचे 68 करोड़ क्विंटल धान में से लगभग 60 करोड़ क्विंटल धान को घोषित एमएसपी से 30 फीसदी कम दाम औसतन 1400 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद कर किसानों का लगभग 78,000 करोड़ रुपये का शोषण किया, यानि केवल वर्ष 2022-23 में ही गलत नीतियों के चलते धान किसानों का लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का शोषण हुआ।

इसी तरह रबी सीज़न 2022-23 में, गेहूं के कुल अनुमानित उत्पादन 111 करोड़ क्विंटल में से 27 करोड़ क्विंटल 2125 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर किसानों से खरीदा गया जबकि सी-2 लागत 1575 रुपये +50 फीसदी लाभ पर गेहूं का दाम 2365 रुपये बनता था। लेकिन किसानों को 240 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम देकर उनका लगभग 6500 करोड़ रुपये का नुकसान किया और साहूकारों ने बाकी बचे 84 करोड़ क्विंटल में से लगभग 70 करोड़ क्विंटल गेहूं एमएसपी से कम दाम (औसतन 1700 रुपये) पर खरीद कर लगभग 46,000 करोड़ रुपये किसानों को हानि पहुंचाई। इस तरह पिछले एक साल 2022-23 में मात्र दो फसलों धान और गेहूं की खरीद से सरकार ने लगभग 50,000 करोड़ और बिचौलियों ने 1,24,000 करोड़ रुपये का नुकसान किया यानि किसानों का कुल दो फसलों के विपणन पर 1,74,000 करोड़ रुपये वार्षिक का शोषण हुआ, जो प्रति किसान लगभग 1.5 लाख रुपये वार्षिक बनता है।

उचित दाम नहीं मिलने से देश में उगाई जा रही 70 से ज्यादा फसलों (अनाज, तिलहन, दलहन, सब्जियों, फलों आदि) के विपणन पर, भारतीय किसानों का लगभग 25 लाख करोड़ रुपये वार्षिक का नुकसान होता है, जो लगभग 2 लाख रुपये प्रति किसान वार्षिक शोषण बनता है। यानी सरकारों की गलत नीतियों के कारण किसानों का लगातार शोषण हो रहा है जिससे किसान दिन-प्रतिदिन गरीब व कर्जदार बनते जा रहे हैं और आत्मघाती कदम तक उठा रहे हैं! दूसरी ओर, मात्र 6000 रुपये वार्षिक किसान सम्मान राशि और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने जैसे जुमलों से प्रचार माध्यमों में वाहवाही लूटी जा रही है! जबकि फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य की 'सी-2 लागत के आधार पर गणना' और एमएसपी गारंटी कानून बनाना ही किसानों की समस्या का स्थाई समाधान है।

किसानों का शोषण करने वाली गलत नीतियों को लगातार जारी रखते हुए, वर्ष 2023-24 खरीफ मौसम की फसलों के लिए, फिर से एमएसपी सी-2 लागत (सम्पूर्ण लागत) पर घोषित नहीं करके, ए2 +एफएल लागत के आधार पर घोषणा की गयी है जिससे किसानों को फिर नुकसान या घाटा ही होना तय है।